

पूरे पुराने बंगाल प्रांत में हिंसा का इतना भयानक दौर पहले नहीं आया

दुष्कर्म मामले में आईपीएल क्रिकेटर को अग्रिम जमानत नहीं मिली

जयपुर, 23 दिसंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी अलका बंसल ने कहा कि आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक गैंग काम कर रही है। उसके खिलाफ पहले गाजियाबाद में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रिकेटर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। इसके सात दिन बाद ही सांगानेर सदर थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया और इसे गंभीर रूप देने के लिए लड़की ने घटना दो साल पहले की बताई जब वह नाबालिग थी। अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि यश दयाल पेशेवर क्रिकेटर है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। इसके अलावा वह प्रकरण की जांच में सहयोग करने को तैयार है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश भर में फैल रहा है अरावली आंदोलन

सचिन पायलट ने राजस्थान के 19 जिलों में अरावली बचाओ आंदोलन की घोषणा की

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। अरावली के मसले पर विरोध प्रदर्शन तीव्र होता जा रहा है और राजनीतिक दल भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं, और पर्यावरणविद् और पर्यावरण से जुड़े एक्टिविस्ट भी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में सड़कों पर उतर आए हैं।

राजस्थान में कांग्रेस ने 19 जिलों में “अरावली बचाओ आंदोलन” का ऐलान किया है, और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि खनन गतिविधियों में वृद्धि से न केवल राजस्थान और हरियाणा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी इकोलॉजिकल संकट उत्पन्न हो सकता है।

शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करते हुए एनडीए सरकार को ”प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने की आदत” की कड़ी आलोचना की है, और अरावली पर्वतों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये पर्वत देश की जलवायु और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुई है, जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित

■ देश भर के पर्यावरणविद्, एक्टिविस्ट व वकील अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे।

■ शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में अरावली का पर्यावरण के लिए महत्व बताया और एनडीए सरकार पर प्राकृतिक संपदाएं नष्ट करने का आरोप लगाया।

■ हालांकि, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मामला शांत करने की कोशिश की और कहा कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर का 0.19 प्रतिशत हिस्सा ही खनन के लिए लीज पर दिया जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर अरावली में अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

■ विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर सरकार की नई परिभाषा को स्वीकार करने से हुई, जिसके तहत जमीन से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। विपक्ष और विशेषज्ञों का आरोप है कि अरावली पर्वत शृंखला में 12,000 पहाड़ियां हैं और इनमें से मात्र 8 प्रतिशत ही 100 मीटर से ऊंची हैं।

अरावली की नई परिभाषा को स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल वे पहाड़ियां जो स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर ऊंची होंगी, उन्हें ही अरावली पहाड़ियां माना जाएगा। ऐसी दो या दो से अधिक

पहाड़ियां जो 500 मीटर के भीतर स्थित होंगी, उन्हें बीच की भूमि सहित अरावली रेंज में माना जाएगा।

एक्टिविस्ट, वकीलों और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंकिता भंडारी मर्डर, एक वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस में आरोप -प्रत्यारोप का नया दौर शुरु कर दिया है

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या के मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व को नए सिरे से जांच के घेरे में ला खड़ा किया है। इस वीडियो ने ताजा आरोपों और सीबीआई जांच की मांगों को जन्म दिया है, जिसमें एक कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की जा रही है।

यह वीडियो, जो पिछले कुछ दिनों से व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, में कथित रूप से हरिद्वार के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश चौहान अपनी पत्नी उर्मिलाना सनावर के साथ तीखी बहस करते दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावा

■ उक्त वीडियो में हरिद्वार के पूर्व विधायक अपनी पत्नी, (पूर्व अभिनेत्री) उर्मिला सनावर के साथ तीखी बहस में यह कहते दिख रहे हैं कि ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में हुई 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या में उत्तराखंड के भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने अंकिता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था।

■ उर्मिला सनावर ने भी सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उसके पास इन आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत भी हैं।

■ कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से सीबीआई जांच करवाई जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपराधियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई।

किया है कि उत्तराखंड के लिए भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम अंकिता भंडारी की हत्या

के पीछे प्रमुख आरोपी थे। चौहान यह आरोप लगाते हुए सुने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति ने 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिये

नयी दिल्ली, 24 दिसम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार– 2025 प्रदान किए।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे संस्करण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए

■ प्रो. जयंत विष्णु नालींकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। खगोल भौतिकी विशेषज्ञ, दिवंगत प्रो. जयंत विष्णु नालींकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डा. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह और सात अन्य को विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रियंका के लिए राहुल से बड़ा ना सही, पर समकक्ष दर्जा चाहता है कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा

इस वर्ग ने कई मायनों में राहुल और प्रियंका के व्यक्तित्व की तुलना की और प्रियंका को “नैचुरल लीडर” बताया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में कदम रखने से पहले, कांग्रेस के लोग उन्हें पार्टी का “ब्रह्मास्त्र” कहते थे, यानी अंतिम हथियार। हालांकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि वह ‘अंतिम हथियार’ अपेक्षाकृत विफल साबित हुआ। फिर भी, कांग्रेस पार्टी मानती है कि राजनीति प्रियंका का “निर्धारित भाग्य” है।

उनके भाई राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, सामान्य रूप से सहजता से उपलब्ध नहीं होते हैं, और इस वजह से कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका पर दांव लगाया।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, प्रियंका ने पार्टी के समर्थकों को निराश नहीं किया, जब उन्होंने वन्दे मातरम विवाद पर

अपना जोशीला भाषण दिया। राहुल गांधी जो अक्सर सदन में अपनी उग्र टिप्पणियों के कारण विवादों में फंस जाते हैं, के विपरीत प्रियंका ने मुस्कुराते हुए सौम्यता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ भाषण दिया और मोदी सरकार पर बढ़त प्राप्त की। यह सौम्यता यही नहीं थी। प्रियंका ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ चाय पर बातचीत की और मित्रता का दायरा और प्रभाव बढ़ाया। रिपोर्टें हैं कि अनुसार, वार्ता में केरल की छह परियोजनाओं पर चर्चा हुई। प्रियंका स्पीकर की चाय पार्टी में भी शामिल हुईं। और वर्ष 2024 चुनाव परिणामों के बाद गांधी परिवार से वे पहली थीं जिन्होंने ऐसा किया। उन्होंने संसद के बाहर इस बारे में विवरण साझा करने में भी संकोच नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि यहां तक कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनकी वन्दे

■ इस थड़े का मत है कि प्रियंका न केवल सहज सुलभ हैं बल्कि अच्छी श्रोता हैं और उनसे डील करना आसान है, इसके विपरीत राहुल आसानी से मिलते नहीं हैं और सिर्फ अपने करीबी गूट के साथ ही सहज रहते हैं, यही नहीं, राहुल बात पूरी सुने बिना ही निर्णय सुना देते हैं और उठकर चले जाते हैं।

■ संसद में भी पक्ष- विपक्ष के सभी नेताओं ने राहुल और प्रियंका के फर्क को देखा। राहुल जहां भाषण देते समय बेहद उग्र हो जाते हैं अक्सर विवादित बातें बोले जाते हैं, इसके विपरीत प्रियंका जोशीला भाषण देती हैं, मजबूती से अपनी बात रखती हैं, किन्तु सौम्यता के साथ।

■ यही नहीं, विपक्ष, खासकर भाजपा नेताओं के साथ बातचीत में भी उनका व्यक्तित्व निखरकर सामने आया, जिसकी मीडिया में भी भारी चर्चा हुई।

मातरम टिप्पणी से प्रभावित थे विडंबना यह रही कि राहुल शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में अनुपस्थित रहे क्योंकि वे भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए जर्मनी गए थे।

कई लोग प्रियंका गांधी को श्रेय देते हैं कि उन्होंने शशि थरूर और मनीष तिवारी, जैसे कांग्रेस नेताओं, जिन्हें राहुल की योजना के तहत लंबे समय से हाशिए पर रखा गया था, को सदन में बोलने का अवसर दिया। प्रियंका के करीबी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सही रूप से कहा: “जब बिल्ली चली जाती है, तो चूहों को खेलने का मौका मिलता है। प्रियंका की बढ़ती सार्वजनिक छवि ने कांग्रेस पार्टी में उग्र बहस को जन्म दिया है, जिसमें लंबे समय से सकारात्मक रूप से कोई बात नहीं हुई है और कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा से दिल्ली और बिहार तक चुनावी हारों के

बाद निराश हो चुकी है। यहां इस मसले पर एकमत है कि कांग्रेस को प्रियंका एक बड़ा सार्वजनिक रोल देना चाहिए, शायद राहुल गांधी के बराबर। कांग्रेस नेता कहते हैं कि वह अपने भाई से कहीं अधिक सुलभ हैं और उनसे डील बहुत अधिक सुखद होता है, साथ ही वह ना कहने की कला में भी माहिर हैं और बड़ी शालीनता से इनकार करती हैं। दूसरी ओर, वरिष्ठ नेता कहते हैं, राहुल गांधी ना तो सुलभ और ना ही सहज हैं, वह केवल अपने करीबी नेताओं के समूह के साथ सहज होते हैं, जो उन्हें “बेकार सलाह” देते हैं; एक नेता ने कहा, “बिना आपकी बात सुने,” राहुल अपना निर्णय दे देते हैं, वो आपको बीच में ही काट देंगे और कमरे से बाहर चले जाएंगे। प्रियंका, इसके विपरीत, एक “अच्छी श्रोता” है इसके लिए उनका सम्मान भी किया जाता है।

घाटे में चल रही पाकिस्तान एयरलाइन नीलाम हुई

इस्लामाबाद, 23 दिसंबर। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन (पीआईए) लंबे समय से घाटे में चलने की वजह से बिक गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे ऊंची, 135 अरब पाकिस्तानी रुपये की बोली लगाकर पीआईए को खरीद लिया है। लकी सीमेंट ने 101.5 अरब रुपये और एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई। पीआईए ने 7.5 फीसदी शेयरों की नीलामी शुरू की थी।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन को नीलामी से मिलने वाले कुल पैसे का 92.5 फीसदी एयरलाइन के सुधार पर खर्च होगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट्स की कमी, खराब मैनेजमेंट और भारी कर्ज जैसे कारणों की वजह से पीआईए की हालत खराब हुई।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने प्रधानमंत्री के सहायक और उनकी टीम को नीलामी प्रक्रिया के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, आज हम जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में बहुत समय और मेहनत लगती है।

विचार बिन्दु

पराधीनता समाज के समस्त मौलिक निमयों के विरुद्ध है। —मान्तेस्कुय

मीडिया में बज़ बनाकर हक़ीकतें बदलने की कोशिश

लोकतंत्र की आत्मा लोक कल्याणकारी शासन में निहित होती है। एक सुशासित राज्य में सरकार करदाताओं के घन से ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाती है जिनका लक्ष्य आम नागरिक के जीवन में ठोस, स्थायी और न्यायपूर्ण परिवर्तन तथा समानता लाना होता है। इस काम के लिए भारतीय संविधान में विधायिका की व्यवस्था है, जिसमें निर्वाचित जन प्रतिनिधि विधियां, नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं जिन्हें कार्यपालिका क्रियान्वित करती है। किंतु इक्कीसवीं सदी के ढाई दशक के बीत रहे काल में आज एक विचित्र और चिंताजनक हालत सामने है। जेन-कल्याण के नाम पर घोषित अनेक कार्यक्रम ज़मीन पर दिखाई नहीं देते, जबकि सरकारें मीडिया में बज़ बनाए रखने के लिए भव्य इवेंट, उद्घाटन, शिलान्यास, उत्सव और प्रचार अभियानों पर अपना अधिकतम ध्यान और संसाधन झोंक रही हैं। यह प्रवृत्ति न केवल कार्यपालिका को शिथिल कर रही है, बल्कि व्यवस्था में पहले से मौजूद भ्रष्टाचार को और गहरा कर रही है। राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में जश्न मनाए जा रहे हैं। राजधानी में सत्ता के शीर्ष से शासन के नीचे तक के तंत्र को स्पष्ट हिदायतें भेजी गई हैं कि इस जश्न के लिए रोज़ कौन-कौन से इवेंट किए जाने हैं। इसके साथ ही प्रलिटिन चौकसी और निगरानी की जा रही है कि जो बातया घटना है वह हो रहा है या नहीं। यहां तक कि कार्यपालिका के प्रमुख मुख्य सचिव खुद जिला अधिकारियों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। अधिकारियों व अन्य कर्मियों को हिदायतें दी गई हैं कि जो भी इवेंट हो उसके चित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाए। प्रचार विभाग की सोशल मीडिया पोस्टों को आगे अपने स्टार पर बढाया जाए। इस की सतत निगरानी होती है और चूक पर फटकारें पड़ती हैं। चाहना यह है कि धरती पर कोई काम हुआ हो या न हो उसके प्रचार का तुफान खड़ा कर दिया जाए। जो इवेंट किए जा रहे हैं उनके परिणामों पर नहीं बल्कि उनके भरपूर प्रचार किए जाने पर एकमात्र जोर है। मान लिया गया है कि धुआं-धारा प्रचार मतदाताओं तक पहुंच कर सत्तारूढ़ दल की मदद करेगा। मुख्य सचिव ने अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा कि बज़ क्रियेट कीजिए। ऐसी बातें प्रचार व्यवसाय को भाती हैं। बाज़ार की ताकतों ने राजनेताओं को यह घुट्टी पिला दी है कि प्रचार की आंधी से चुनाव जीते जा सकते हैं। यह कोई याद नहीं दिलाता कि पिछली अशोक गहलोत की सरकार ने फिर कुर्सी पाने की ताबड़तोड़ में प्रचार के भ्रष्टाचार का जो अंबार खड़ा किया उस पर मतदाता की समझ भारी पड़ी थी। बाज़ार के सौदागरों ने नई सरकार को भी प्रचार के चमक-दमक की बही राह दिखा दी है जिस पर होर्डिंस बही है, केवल राजनेताओं के चित्र बदले हुए हैं। जनकल्याण का अर्थ होता हैनिरंतरता, निगरानी, जवाबदेही और परिणाम। इसके विपरीत, इवेंट-आधारित शासन का मूल तत्व होता है दिखावा, सुर्खियां और छवि-प्रबंधन। सड़क, स्कूल, अस्पताल, पानी, स्वच्छता, पोषण, रोज़गार जैसे क्षेत्रों में सुधार का असर महीनों-सालों में दिखता है; जबकि एक भव्य कार्यक्रम का प्रभाव कैमरों की चमक तक सीमित रहता है। यही कारण है कि प्रदर्शनकारी शासन त्वरित संतोष देता है। उसके नेताओं को तालियां, प्रशंसा को फोटो-ऑप्स और सत्ता को कथानक (नैरेटिव) मिल जाता है। परिणामस्वरूप, लोक-कल्याण का वास्तविक काम पीछे छूट जाता है।

भ्रष्टाचार का पोषण प्रशासनिक शिथिलता से होता है। जब शासन का केंद्र बिंदु परिणाम नहीं, बल्कि प्रस्तुति बन जाए, तो भ्रष्टाचार के लिए उर्वर भूमि तैयार होती है। इवेंट-आधारित मॉडल में टेके, टेंट, लाइटिंग, विज्ञापन, ब्रांडिंग, यात्रा और आतिथ्य, इन समस्त त्वरित भुगतान, कम पारदर्शिता और आपात निर्णयों की खूब गुंजाइश रहती है। यह कम समय-अधिक खर्च का वह रास्ता है जहां कमोशान संस्कृति सहज ही फलती-फूलती है। इसके विपरीत, किसी स्कूल की गुणवत्ता सुधार या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यक्षमता बढ़ाने में निरंतर निरीक्षण, ऑडिट और सामुदायिक सहभागिता चाहिए जो इवेंट की तुलना में कम आकर्षक होती है। कार्यपालिका की शिथिलता इसी बिंदु से जन्म लेती है। अधिकारियों का मूल्यंकन परिणामों से नहीं, बल्कि कार्यक्रमों की सफलता या कवरेज से होने लगता है। ऐसे में फोल्ड वर्क गौण हो जाता है। फाड़लें चलती हैं,

इवेंट-लोकतान्त्रिक शासन का विकल्प

नहीं हो सकते। सत्ता में बैठे राजनेताओं

को याद रखना होगा कि इतिहास मंच-

सज्जा नहीं, परिणाम लिखता है।

शासन को फिर से सेवा, सत्य और

जवाबदेही के अपने मूल कर्तव्य की ओर

लौटने से ही लोकतंत्र फल-फूल सकता

है। यही लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्र के

भविष्य का एकमात्र मार्ग है।

पर धकेल दिया जाता है। इस नैरेटिव-निर्माण में आंकड़ों की बाज़ीगरी, चयनित उपलब्धियां और आलोचनाओं का दमन शामिल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि किसी दैनिक अखबार में किसी दिन सत्ता के नेतृत्व की उपलब्धियों के 13 पूरे पेजों के विज्ञापनों से नागरिकों को काम हुआ का भ्रम मिलता है, जबकि वास्तविकता अलग होती है। इवेंट-शासन संस्थाओं को कमजोर करते हैं। दुर्भाग्य से संस्थागत क्षरण और लोकतांत्रिक नुकसान अब किसी को नज़र नहीं आते।नीति निर्माण में विशेषज्ञता और डेटा का स्थान नारे ले लेते हैं। संसद-विधानसभाओं में बहस की जगह हंगामों के बीच घोणाएं हावी हो जाती हैं। स्थानीय निकाय, जो जनकल्याण की रीढ़ होते हैं, उपेक्षित रहते हैं; क्योंकि वहां स्थानीय राजनीति के पच्चेडे होते हैं और उनकी उपलब्धियों की ज़मीनी हक़ीकत नागरिक रोज़ महसूस करते हैं जो किसी मंच-सज्जा से झुलझाई नहीं जा सकती। लोकतंत्र में नागरिक लाभाभी नहीं, हितधारक होते हैं। लेकिन जब शासन प्रदर्शन में बदल जाए, तो नागरिक दर्शक बन जाते हैं। वे आमंत्रित तालियां बजाने वाले हो जाते हैं। वे सवाल न पूछने वाले नागरिक बन दिए जाते हैं। यह व्यवस्था किसी को नहीं चुनौती, क्योंकि सभी के लिए यह सुभीती वाली होती है। संसाधनों की बर्बादी और लागत पर बुद्धिजीवियों का भी ध्यान नहीं जाता है। वे भी अपने-अपने इवेंट में व्यस्त रहते हैं। इवेंट और प्रचार पर किया जाने वाला धन यदि स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण, अस्पतालों में उपकरण, जल-प्रबंधन या रोज़गार-सृजन के कार्यों पर लगे, तो स्थायी लाभ मिल सकता है। कोई यह कहने वाला नहीं मिलता है कि शासन की प्राथमिकताएं बदल जाने का दीर्घकालिक नुकसान अंततः समाज को ही होता है। गरीबी के चक्र, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट को नज़रन्दाज़ करते हुए भविष्य की कीमत पर सत्ता अपने वर्तमान को चमकाने का प्रयास कर रही है। इस व्यवस्था में समाज में आर्थिक असमानता और नागरिकों में बेचैनी बढ़ती है, अपराधों का बोलबाला होता है। बड़ा नुकसान जवाबदेही के तंत्रों के क्षय का होता है। इवेंट-शासन में जवाबदेही धुंधली हो जाती है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, समय-सीमा ढीली रहती है और मापन के पैमाने बदल दिए जाते हैं। कितने कार्यक्रम हुए की गणना वीडियो कॉन्फ्रेंसों के जरिए होती है। सार्वजनिक सेवाओं में कितना सुधार हुआ की कोई गणना नहीं होती। कोई पूछता भी नहीं। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्टें अनसुनी रह जाती हैं। शिकायत-निवारण तंत्र निष्प्रभावी हो जाते हैं। प्रचार से असफलताओं को ढक दिये जाने वाले निज़ाम में सुधार की प्रेरणा की कल्पना कैसे की जा सकती है! ऐसे में सामाजिक और लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठने लगता है। सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास ही शासन की पूंजी होती है। बार-बार के वादे, भव्य घोणाएं और ज़मीनी नाकामी इस विश्वास को क्षत-विक्षत कर देती हैं। लोग व्यवस्था से विमुख होते हैं, निराशा और आक्रोश बढ़ता है। कानून को धत्ता बताई जाने लगती है। अपराध सामान्य चलन बन जाता है। यह सब मिल कर अंततः सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक स्थिरता-दोनों के लिए खतरनाक हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि समाधान की कोई दिशा न हो। परिणाम-आधारित शासन के लिए ज़मीन तैयार करनी होगी। इसके लिए राजनीतिक रूझावशक्ति और नागरिक दबाव साथ ही तभी बात बन सकती है। शासन में परिणाम-आधारित मूल्यंकन से ऐसा हो सकता है। अधिकारियों और विभागों का आकलन स्पष्ट, मापने योग्य परिणामों से हो, जैसे सीखने के स्तर, स्वास्थ्य संकेतक, सेवा-डिलीवरी समय आदि। सरकारों खर्चों में पारदर्शिता हो। इवेंट और प्रचार व्यय पर सीमा तय हो और सभी खर्च सार्वजनिक डैशबोर्ड पर साफ-साफ दिखें। समयबद्ध ऑडिट, सामाजिक ऑडिट और स्थानीय समुदाय की भागीदारी अनिवार्य हो। यहां मीडिया की जिम्मेदारी आती है। उसे विज्ञापन-समाचार की स्पष्ट रेखा खींचनी होगी और ज़मीनी रिपोर्टिंग की अहमियत समझनी होगी। स्थानीय निकायों के काम काज की निगरानी में नागरिकों की भागीदारी बनानी होगी। वर्तमान चुनावी व्यवस्था के बाहर भी कुछ करना होगा। कानूनी जवाबदेहीभी ज़रूरी है भ्रष्टाचार और लापरवाही पर त्वरित दंड मिले और व्हिस्लब्लोअर को सुरक्षा मिले। मगर असली बात होगी नागरिक जागरूकता। नागरिक सवाल पूछें और खड़े होकर कह सकें कार्यक्रम नहीं, परिणाम दिखाइए। इवेंट-लोकतान्त्रिक शासन का विकल्प नहीं हो सकते। सत्ता में बैठे राजनेताओं को याद रखना होगा कि इतिहास मंच-सज्जा नहीं, परिणाम लिखता है। शासन को फिर से सेवा, सत्य और जवाबदेही के अपने मूल कर्तव्य की ओर लौटने से ही लोकतंत्र फल-फूल सकता है। यही लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्र के भविष्य का एकमात्र मार्ग है।

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल

बुधवार 24 दिसम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

आज रविवोग प्रातः 8:18 से आरम्भ होगा। भद्रा आज दिन 1:12 तक रहेगी। पंचक सायं 7:46 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:52 तक, शुभ 11:09 से 12:26 तक, चर 3:01 से 4:18 तक, लाभ 4:18 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:17, सूर्यास्त 5:35 तक



मेष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करो। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।



तुला

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में वृद्धि होगी।



वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मिथुन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज नवीन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।



धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरिपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।



मकर

व्यावसायिक कार्य से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरिपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।



सिंह

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।



कुंभ

आज समय अनर्गल कार्यों में व्यतीत होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।



कन्या

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।



मीन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

अरावली पर्वत श्रृंखला: अस्तित्व का संकट और भविष्य



अशोक कुमार

अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। आज, 2025 के परिप्रेक्ष्य में, अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं रह गई है, बल्कि यह उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के लिए अस्तित्व की जीवन रेखा बन चुकी है। इसे “दिल्ली-एनसीआर के फेफड़े” कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में यह फेफड़े शहरीकरण, अवैध खनन और प्रशासनिक अनदेखी के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

अरावली धार मरुस्थल की उड़ती हुई रेत को गंगा के उपजाऊ मैदानों और दिल्ली-एनसीआर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करता है। यदि यह पहाड़ियां गायब हो गईं, तो उपजाऊ कृषि भूमि

मरुस्थल में बदल जाएगी। अरावली की दरारयुक्त चट्टानी संरचना वर्षा जल को जमीन के नीचे भेजने के लिए एक स्पंज की तरह काम करती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के गिरते भूजल स्तर के बीच, अरावली ही एकमात्र माध्यम है जो एक्विफर को रिचार्ज करता है। एनसीआर क्षेत्र दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार है। अरावली के घने जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने का प्राथमिक स्रोत है। यह क्षेत्र तेंदुओं, नीलगाय, सियार, धारीदार लकड़बग्घा और पक्षियों की सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। यह राजस्थान के सरिस्का से लेकर हरियाणा के असोला भट्टी तक वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित गलियारा प्रदान करता है।

राजस्थान में अरावली का विस्तार सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ यह माफियाओं के निशाने पर है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एकरिपोर्ट ने देश को झकझोर दिया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियाँ पूरी तरह गायब हो चुकी हैं।

2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, अवैध खनन की यह समस्या और गंभीर हुई है। पहाड़ियों के समतल होने के कारण धूल भरी आंधियों की तीव्रता अब साल के अधिकांश समय दिल्ली को प्रभावित करती है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में

स्थिति और भी विकट है। यहाँ पहाड़ियों को काटकर आलीशान फार्महाउस और अवैध रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। अरावली नोटिफिकेशन (1992) के बावजूद, जमीनी स्तर पर नियमों का उल्लंघन आम है। अरावली को बचाने के मार्ग में आज कई नई और जटिल चुनौतियाँ खड़ी हैं: भवन निर्माण के लिए पत्थर और रेत की मांग ने अरावली को छलनी कर दिया है। रात के अंधेरे में डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ाया जाना पारिस्थितिक तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँचा रहा है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण पहाड़ियों के बड़े हिस्से को काटा गया है। इसके अलावा, एनसीआर की बढ़ती जनसंख्या के दबाव में जंगलों को समतल मैदान में बदला जा रहा है। अक्सर 'वन' की परिभाषा को लेकर विवाद होता है। हाल के वर्षों में वन संरक्षण संशोधन अभिनियम को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, जिससे अरावली के गैर-वर्गीकृत वन क्षेत्रों पर विकास कार्यों का खतरा मंडराने लगा है।

अरावली के मूल पेड़ों जैसे ढाक, खैर, और बबूल की जगह विलायती कीकर ने ले ली है। यह प्रजाति भूजल को तेजी से सोखती है और स्थानीय वनस्पतियों को पनपने नहीं देती।

अरावली को बचाने के लिए

वर्तमान में तीन स्तरों पर लड़ाई लड़ी जा रही है:सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि “अरावली में कोई भी गैर-वानिकी गतिविधि नहीं होगी।” कोर्ट ने हरियाणा सरकार को खोरी गाँव जैसे अतिक्रमण हटाने और वन भूमि को पुनर्जीवित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार ने अरावली के किनारे 1,400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी अरावली ग्रीन वॉल बनाने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पोरबंदर से पानीपत तक वृक्षारोपण के माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोकना है।

अरावली बचाओ सिटिजन मूवमेंट, अरावली बचाओ जैसे संगठनों ने लोगों को जागरूक किया है। युवाओं और पर्यावरणविदों द्वारा सोशल मीडिया और पदयात्राओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अरावली को “इको-सेंसिटिव जोन” के रूप में पूरी तरह सुरक्षित किया जाए।

अरावली को केवल कागजी कानूनों से नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए एक समटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है: सेटेलाइट इमेजरी और ड्रोन के जरिए अरावली की सीमाओं का सटीक सीमांकन किया जाए ताकि एक इंच भूमि पर भी कब्जा न हो सके।विदेशी पेड़ों को हटाकर स्वदेशी प्रजातियों के जंगल विकसित किए जाएं जो जल

संचयन में सहायक हों। अरावली को बिना नुकसान पहुँचाए ट्रेकिंग और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के लिए विकसित किया जाए। जब स्थानीय लोगों को पर्यटन से रोजगार मिलेगा, तो वे स्वयं इन पहाड़ियों के रक्षक बनेंगे। जिन क्षेत्रों में खनन के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं, वहाँ जल संचयन पहाड़ियों के स्थान पर कृत्रिम घने वन विकसित किए जाएं।

अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाए जाएं और उनकी संपत्तियां कुर्क करने जैसे कड़े प्रावधान हों।

अरावली पर्वत श्रृंखला कोई निर्जीव पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। आज हम जिस ताजी हवा और पीने योग्य पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी चाबी अरावली के पास है। यदि हमने स्वार्थ और विकास की अंधी दौड़ में अरावली को छो दिया, तो आने वाली पीढ़ियां एक मरुस्थलीय और जहरीली हवा वाले भारत में सांस लेने को मजबूर होंगी। अरावली को बचाना अब केवल पर्यावरण प्रेमियों का शौक नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

—अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल 2025 का समापन

पाली, (निसं)। मारवाड़-गोड़वाड़ की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करने की मंशा से जिला प्रशासन पाली, पर्यटन विभाग राजस्थान तथा नगरपालिका सादड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल 2025 का रंगारंग समापन हुआ।

इस अवसर पर महोत्सव में पर्यटक वन्यजीवों को प्राकृतिक पर्यावास में देखकर रोमांचित हो उठे। इधर, रणकपुर स्थित हॉट एयर बैलुनिंग आयोजित हुआ। हेलीपैड ग्राउंड पर ही आयोजित रोचक प्रतियोगिताओं में भी सैलानियों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दिन हॉर्स शो आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने सजे ध्वजे घोड़ों के करतबों पर दांतों तले उंगली दबा ली। हॉर्स पोलो के दौरान दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। वहीं दिनभर चली रोचक प्रतियोगिताओं और हॉर्स शो ने भी सैलानियों को रोमांचित किया।

महोत्सव में रस्साकस्सी की महिला को प्रथम टीम में सुमन, सोनल, सीता, रेशमा, आशवंती, लक्ष्मी, आकांक्षा, दीपिका, कंचन, ललित, चम्पा प्रथम रही। इसी प्रकार पुरुष की रस्साकस्सी टी में रमेश चंद्र परिहार, रानुसिंह, रामेश्वर फिरोदा, बाबूलाल माली, ललित माली, मुकेश दवासी,



मिस गोडवाड़ प्रतियोगिता के विजेता को अधिकारियों ने पुरस्कृत किया।

पप्पु कुमार, जावेद टांक, भंवरलाल, नकुल कश्यप व जीतू चौधरी टीम प्रथम रही। गोडवाड़ श्री में प्रशांत वर्मा प्रथम एवं मिस गोडवाड़ में शारदा कुमार प्रथम रही। मूछ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर विक्रमसिंह, रॉसिंह चौहान प्रथम रहे, द्वितीय स्थान पर संदीप राठीड, तृतीय स्थान पर पोंकरलाल सोलंकी, धीरेन्द्र सिंह, देवा मारवाडी तृतीय रहे। साफा बांध प्रतियोगिता में संजय मंशान प्रथम, तेजवंत सिंह चौहान द्वितीय, तृतीय डिकेन्द्र सिंह सिन्हादिया,

यूथिष्ठर चौहान, मादामार तृतीय रहे। चम्पन दौड़ में आदित्य सिंह प्रथम, रमेश द्वितीय व पदमिनी तृतीय नम्बर पर रही तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता में राजकुमार सोनी प्रथम, शुभम सोनी द्वितीय एवं आदित्य कंसारा तृतीय रहे। मटका दौड़ में प्रथम गुणिता देसूरी, द्वितीय कन्या सोनाना, तृतीय शारदा रही, इसके साथ ही अन्य स्पर्धाएं भी आयोजित हुईं।

फेस्टिवल में जिला कलैक्टर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के

तत्वावधान में फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी हुई। इसमें जिले भर के फोटोग्राफर्स ने प्राकृतिक, वाइल्डलाइफ, कल्चर व सांस्कृतिक विषय पर फोटोग्राफी कर प्रविष्टियां जमा कराईं। इन सभी फोटोग्राफर्स की यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे दर्शकों ने देख के सराहा। फेस्टिवल के अंतिम दिन रात सूर्य मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में मामले खान के सुरों ने समा बांध दिया। मामले खान ने पधारों मारे देश गीत से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। साथ

■ फेस्टिवल में रोचक प्रतियोगिताओं और हॉर्स शो ने रोमांचित किया

■ सूर्य मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में मामले खान के सुरों ने समा बांधा

ही रामचन्द्र अवतार लियो..., चंदे मातरम....., जब देखे बुरे री लाल पीली अंखिया....., केशरिया बालम...., चमचम चमके चुनड़ी बनजारा रे... आदि गीतों की प्रस्तुति दी। उसमें दर्शकों का उत्साह देखते ही बना।

इस अवसर पर पशुपालन, डेयरी, देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री जोरामान कुमावत, संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह, जिला कलक्टर एलएन मंत्री, प्रशिक्षु आईएएस बिरजु गोपाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ बजरंगसिंह, बाली अतिरिक्त जिला कलक्टर शेलेन्द्रसिंह, उपखण्ड अधिकारी देसूरी सिद्धार्थ सांदू, नगरपालिका ईओ सादवी, संयुक्त निदेशक पर्यटन भानु प्रताप, सेलो ग्रुप के प्रतिनिधि नरेश ओझा, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक सरिता फिंडोदा एवं अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

5 वीं-8 वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी

बीकानेर, (निसं)। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 वीं और कक्षा 8 वीं बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम जारी कर दिया है। शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा (कक्षा 5) का आयोजन आगामी वर्ष फरवरी से मार्च के बीच में किया जाएगा।

आठवीं के स्टूडेंट्स को होली के अवकाश में भी तैयारी करनी

होगी, जबकि पांचवीं के स्टूडेंट्स के एग्जाम पहले ही खत्म हो जाएंगे। सिर्फ संस्कृत स्कूल सहित विशेष स्कूलों में ही पांचवीं की तृतीय भाषा के एग्जाम होंगे।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8 वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी, जबकि कक्षा 5 वीं की परीक्षाएं 20

फरवरी 2026 से 5 मार्च तक आयोजित होंगी।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विभागीय पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

कंटेनर में भरे गौवंश को मुक्त कराया

टोंक, (निसं)। निवाई क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस और गौ सेवादल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर सोमवार रात्रि को दो दर्जन गौवंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। भ्रातृ जनकपुर के अनुसार सोमवार रात्रि को गौवंश सेवादल को गांव चिकाना क्षेत्र से गौवंश से भरा

सरकार हर बेटी, हर महिला के साथ

सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की पक्की बात

हर बेटी, हर महिला के साथ... यह सरकार की वह प्रतिबद्धता है, जो संवेदनशीलता को नीति और संकल्प को परिणाम में बदलती है। महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक मजबूत ढांचे में पिरोया है। ये पहल केवल सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान कर रही हैं। स्वच्छ रसोई की सुविधा से लेकर उच्च शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक संबल से लेकर सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर निर्भीकता, सरकार का प्रयास है कि हर बेटी और हर महिला को बराबरी का अवसर और सम्मान मिले। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए एक समावेशी, सशक्त और संवेदनशील समाज की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।



आगे बढ़ रही बेटी

राजस्थान में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत 33,904 बेटी जन्मोत्सव समारोह आयोजित किए गए हैं। इसमें 1.95 लाख बालिकाओं के जन्मोत्सव मनाए गए तथा ग्राम पंचायतों पर 2.72 लाख वृक्षों का रोपण किया गया। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की बेटीयों को वित्तीय सहयोग देना है जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई कर रही हैं। आपकी बेटी छात्रवृत्ति योजना राजस्थान में हर पात्र छात्रा को 2,100 से 2,500 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

सरकार की पहल से आसान हुई खेती



व्याज-मुक्त फसली ऋण सुविधा के माध्यम से सरकार किसानों को किरायाती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की बड़ी पहल कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 77.74 लाख से अधिक किसानों को 44,355 करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को व्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे उनकी खेती की लागत घटाना आसान होता है और बीज, खाद व कीटनाशक जैसी आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो पाती है। नवीन कृषकों को 446.24 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए गए हैं।

634.22 करोड़ रुपये के ऋण



डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक लाख रुपये तक व्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इसमें 84,604 पात्र गोपालक परिवारों को 634.22 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। सभी दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है।

गांव-गांव पहुंचा उपचार

मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट पशुपालन विभाग की ऐसी पहल है, जिसके जरिए दूरदराज गांवों में पशुओं को चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 536 मोबाइल वाहनों से करीब 58.64 लाख पशुओं का उपचार कर 14 लाख 48 हजार से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।



- रसोई गैस सब्सिडी योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध
- कृषि अध्ययन के लिए 58,397 छात्राओं को 103 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
- लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.50 लाख रुपये सेवा बॉण्ड से 4.60 लाख बालिकाओं को मिला लाभ
- 12 लाख महिलाएं बर्नी लखपति दीदी, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 216 करोड़ रुपये के ऋण
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 9.92 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की सहायता
- महिला अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी, 65 एन्टी रोमियो स्कवॉड का गठन



हर नारी का मान

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना द्वारा विधवा, परित्यक्ता, अकेली महिलाओं व जरूरतमंद महिलाओं को मासिक पेंशन, आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना में करीब 6,234 करोड़ रुपये व्यय कर 19.24 लाख पेंशनर्स को लाभ दिया गया है।

दीदी बनी लखपति

प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राजीविका मिशन के तहत 'लखपति दीदी' योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत करीब 19.45 महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण प्रदान कर 12.06 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।

बिटिया की शिक्षा की राह हुई सुगम

सरकार ने कालीबाई भील निशुल्क स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूटी की राशि सीधे संबंधित एजेंसी के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। योजना में 39,664 स्कूटियों का वितरण किया गया है।

महिला सुरक्षा- एक और बढ़ा कदम



राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'कालिका पुलिसकर्मियों' की 500 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' का गठन किया है। ये टीमें राज्य के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, जैसे कॉलेज, मॉल और धार्मिक जगहों पर गश्त करती हैं। यूनिट की वर्दी को खास डिजाइन किया गया है। इनके स्कूटर और हेलमेट काले रंग के हैं और वर्दी पर पीछे की ओर नियाँ मोनोग्राम होता है।

स्वच्छ ईंधन से सेहत

गरीब परिवार की महिलाओं को हानिकारक धुएं से बचाकर स्वस्थ प्रदान करने के लिए एक जनवरी, 2024 से रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चिह्नित लाभार्थियों तथा बीपीएल परिवारों (राजस्थान राज्य के) को रसोई गैस सिलेण्डर केवल 450 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों को 4.82 करोड़ गैस सिलेण्डर सिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

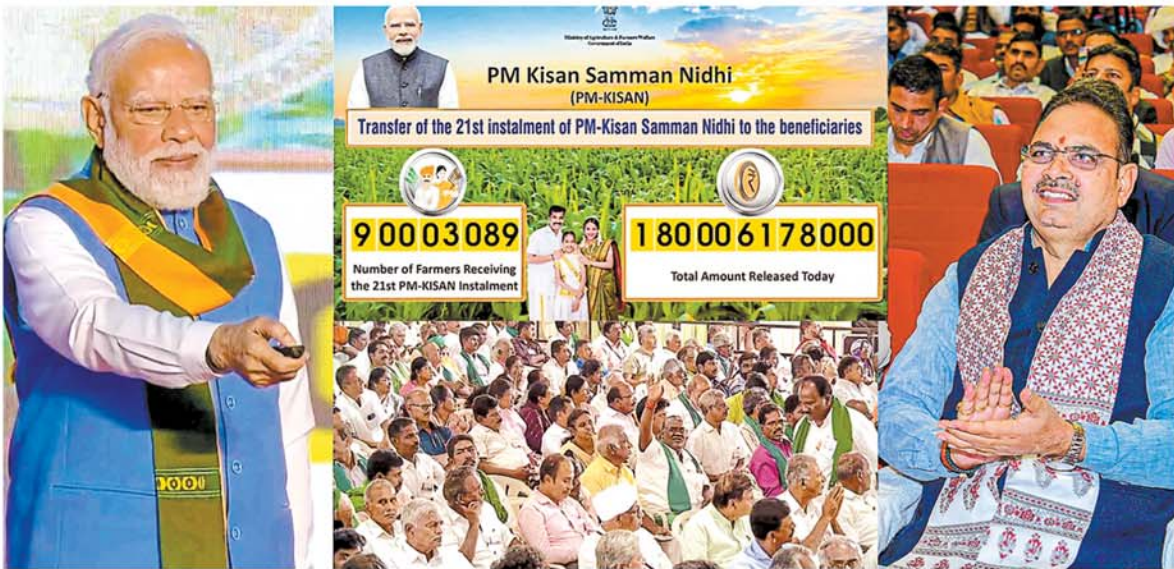
खिलखिला रही लाडो

लाडो प्रोत्साहन राशि पहले एक लाख थी जिसे भजनलाल सरकार ने बढ़ाकर अब 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 4.60 लाख बालिकाएं प्रथम क्रिस्त से लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना में परिवार को राजस्थान में बेटी के जन्म पर सेविंग बॉन्ड कुल सहायता राशि 1.5 लाख कुल 7 किस्तों में (जन्म, टीकाकरण, स्कूल-प्रवेश, कक्षा-उत्थान, स्नातक आदि के समय) दी जाती है। यह योजना स्वचलित है और इसके लिए अलग से फार्म भरने की जरूरत नहीं है।

किसान और पशुपालक के हित में ठोस प्रयास

खेत से घर तक विकास की नीति बनी ग्रामीण उत्थान का मजबूत आधार

ग्रामीण अंचलों की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए और किसानों-पशुपालकों के हर संघर्ष को अपना दायित्व मानते हुए राज्य सरकार ने विकास की ऐसी समग्र रूपरेखा तैयार की है, जिसमें सेवा, सुरक्षा और सशक्तीकरण तीनों का संतुलित समावेश दिखाई देता है। खेती और पशुपालन को केवल आजीविका नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर सरकार ने नीतियों को जमीन से जोड़ते हुए उन्हें परिणामोन्मुख बनाया है। दूरदराज गांवों और रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच हो, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिले, फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिले, सिंचाई और बिजली की समस्याओं का समाधान हो या फिर डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करनी हो, हर मोर्चे पर सरकार की मंशा स्पष्ट और प्रयास प्रभावी नजर आते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि किसानों और पशुपालकों में विश्वास, आत्मबल और भविष्य के प्रति आश्वस्ति भी पैदा की है। ये पहल इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार का विकास मॉडल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव की चौपालों तक उपस्थिति दर्ज करा रहा है।



76.18 लाख किसानों को मिला 'सम्मान'

राज्य में वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ करने की घोषणा के बाद लाभार्थियों को हर साल 2,000 रुपये तीन किस्तों में देने की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 2,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 2025-26 में 3,000 रुपये कर दिया। योजना में किसानों को हर साल तीन किस्तों में 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक योजना में 71.79 लाख किसानों को 2,073 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के 76.18 लाख किसानों को अब तक 8 हजार 359 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

खेती, पशुपालन और तकनीक का अपूर्व संगम

जनकल्याण से कृषक आत्मनिर्भरता तक समावेशी विकास



हर मुश्किल में सरकार साथ

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में किसानों को खेती करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अंग-भंग होने की स्थिति में आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है। योजना में 5,415 लाभार्थियों को 85.41 करोड़ रुपये की सहायता की गई है। इसके अलावा पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य में देश की सबसे अधिक क्षमता वाली विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।



बढ़कर मिल रहा बोनस

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपये एवं वर्ष 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 150 रुपये का बोनस प्रदान कर 2575 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदकर किसानों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में 2.66 लाख किसानों से 33.42 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उन्हें 471.16 करोड़ रुपये बोनस दिया गया है।



तारबंदी योजना से मिली सुरक्षा

तारबंदी योजना के अंतर्गत आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों के खेतों में फेंसिंग (तारबंदी) पर अनुदान दिया जाता है। किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित है। लघु एवं सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत तक, अधिकतम 48 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। करीब 31,357 किलोमीटर की तारबंदी स्थापित कर 330 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान दिया गया है।



किसान की नई डिजिटल पहचान

किसान डिजिटल आइडी के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 75 लाख किसानों को यह डिजिटल पहचान उपलब्ध कराई जा चुकी है। इससे लाभार्थी सत्यापन सरल हो गया है, योजनाओं का लाभ एक क्लिक पर मिल जाता है। एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत डिजिटल कृषि पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राफ्ट सर्वे गिरदावरी योजनाएं शुरू की गईं।

6206.61 करोड़ के क्लेम वितरित



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लागू की गई है। योजना में किसानों की फसल को बुआई से लेकर कटाई होने के बाद तक आने वाली मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा दी जाती है। इससे किसान बिना डर के खेती कर सकते हैं और नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा भी मिलता है। बीते दो साल में योजना के तहत अब तक 6206.61 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं एवं देश में सर्वाधिक 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियों का सृजन किया गया है।

पैसों के विवाद में महिला के गले और सिर पर वार कर हत्या की थी

जयपुर। भारत रत्न से सम्मानित, किसान मसीहा एवं पूर्व प्रधामंत्री स्व. चौधरी बलवंत सिंह की 123वीं जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से यह कार्यक्रम जयपुर में पिंकसिटी ग्रेस क्लब में किया गया। समारोह अध्यक्षता राजस्थान प्रदेशस्थान अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने की। समारोह में किसानों के अधिकारों पर सम्पूर्ण एवं सशक्तिकरण को लेकर सार्थक, सकारात्मक एवं विचारोत्तेजक संवाद हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक चार्गाण तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाभाशाह विज्ञान-पूजिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि त्रिलोक चार्गाण ने भारत रत्न स्व. चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवान सहित प्रदेश प्रदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। त्यागी ने कहा कि आरएलडी प्रदेश के सभी जिलों में स्व. चौधरी चरण सिंह के विचारों पर संगोष्ठी करेगी।

मुख्यमंत्री व शिवराज सिंह ने मेड़ता में किसानों को 1 2 0 0 करोड़ रु. हस्तांतरित किये

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2000 करोड़ रु. के स्वीकृति पत्र सौंपे

नागौर/जयपुर, 23 दिसम्बर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि किसानों का फसल उत्पादन बढ़े तथा उनकी लागत में कमी आए।

चौहान मंगलवार को राज्य

■ किसान सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट तथा पैस्टिसाइड एक्ट लाने वाली है, जिससे नकली पैस्टिसाइड व महंगे बीज देने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी।

सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत दो वर्षों में राजस्थान में विकास का नया अध्याय रचा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर 9 हजार रुपये किया है।

चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट एवं पैस्टिसाइड एक्ट लाने वाली है जिससे नकली पैस्टिसाइड एवं महंगे बीज देने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है तथा शीघ्र ही वंचित गरीबों को मकान देने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है तब अन्नदाता अपने खेतों में जागते हैं।



केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरु ने मुख्यमंत्री को हल भेंट किया।

चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या आंधी तूफान, किसानों का काम कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक किसान रहे हैं इसलिए वे खेती में आ रही समस्याओं को भली-भांति समझते हैं।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली जैसे अनेक किसान हित में निर्णय लिए

हैं। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले बैच में 3 हजार 200 किलोमीटर से अधिक की 1,216 सड़कों एवं एक पुल के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये के कार्यों का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण योजनाओं के तहत 35 हजार 800 किसानों को 187.60 करोड़ रुपये की राशि उनके

खातों में हस्तांतरित की। साथ ही, 5 लाख कृषकों को कृषि आदान अनुदान के रूप में 617 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि भी खातों में भेजी गई।

उन्होंने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को 150 करोड़ रुपये की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 18 हजार 500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की।

बांग्लादेश उच्चायोग पर भारतीयों का गुस्सा फूटा

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में कहा, “बांग्लादेश इस तरह की पूर्व-नियोजित हिंसा या राजनयिक प्रतिष्ठानों को डराने-धमकाने की घटनाओं की निंदा करता है, जो न केवल राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि आपसी सम्मान और शांति व सहिष्णुता के

मूल्यों को भी कमजोर करती है।”

मंत्रालय ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इससे राजनयिक कर्मियों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा है और भारत से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

बयान में कहा गया, “बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया

है कि वह इन घटनाओं की गहन जांच कराए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और भारत में बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।”

इन घटनाओं में 22 दिसंबर 2025 को सिलीगुड़ी स्थित बांग्लादेश

देश भर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उत्तरकर विरोध प्रदर्शन किया है, उनका कहना है कि सरकार अरावली को खनन माफिया और भूमाफियाओं को बेचने की कोशिश कर रही है, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाने का बड़ा जोखिम पैदा करेगा।

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस डर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि जब तक एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार और अनुमोदित नहीं की जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली में से केवल 0.19 प्रतिशत ही खनन के योग्य है। अवैध खनन के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए मंत्री ने कहा कि नया नियम ऐसे कार्यों पर नियंत्रण लगाएगा और “कानूनी रूप से सतत खनन” की अनुमति देने के उद्देश्य से है। हालांकि, उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अवैध खनन गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जाएगी। एक्विविस्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अरावली की नई परिभाषा के कारण स्थिति ऐसी बन जाएगी कि 90 प्रतिशत पहाड़ियां अब अरावली के रूप में नहीं मानी जाएंगी। मंत्री ने यह स्पष्ट करने में विफलता जताई कि कितनी पहाड़ियां संरक्षित की जाएंगी और कितनी प्रभावित होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2010 में फॉरेस्ट सर्वे इंडिया भारत की एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि अरावली की लगभग 12,000 पहाड़ियों में से केवल 8 प्रतिशत पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं।

दुष्कर्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील रचना मान ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए हैं।

पूरे पुराने बंगाल प्रांत में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोषियों को सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं, पुलिस थाने आम तौर पर मुस्लिम अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर देते हैं।

इसके बावजूद, ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब उनके लिए पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही है। एक मुस्लिम, जो मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ को कम कर रहा है वह उन्हीं के जैसा एक व्यक्ति है और उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। हुमायूँ कबीर नामक एक दलबदलू नेता, जो पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता रहा है, ने अब अपनी नई पार्टी बना ली है और अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे रहा है। कबीर ने पहले मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं को “काटने” और लाशों को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की धमकी दी थी। उसने यह दावा किया था कि मुर्शिदाबाद की आबादी में 80 प्रतिशत मुस्लिम हैं।

पश्चिम बंगाल से भी कहीं ज्यादा भयावह हालात बंगाल के दूसरे हिस्से, यानी बांग्लादेश में हैं, जहां इतनी हिंसा फैल चुकी है जो हाल के वर्षों में शायद ही कभी देखी गई है। कट्टर इस्लामी भीड़ देश में तबाही मचा रही है और हिंदुओं पर हमले बेहिसाब बढ़ गए हैं।

बांग्लादेश में एक हिंदू गारमेट मजदूर की नृशंस हत्या ने भारत में गंभीर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। हैरानी

- बांग्लादेश में इस्लामिक जूनून, जो पाकिस्तानी व बांग्लादेश के जमाती धर्मालम्बियों के आपसी सहयोग से चरम पर पहुंच गया है, का निशाना भी उस देश में रहने वाला आम हिन्दू ही है।
- यह माना जा रहा है कि यह हिंसा का दौर, प.बंगाल के चुनाव तक यँ ही बढ़ता जायेगा, पर फिर क्या इस नाग को दोबारा पिटारी में बंद किया जा सकेगा।

की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस घटना का लगभग कोई असर नहीं दिखा और शायद ही कोई इसकी परवाह कर रहा है। यह ममता बनर्जी और उनकी तुणमुल कांग्रेस के आदेशों के आगे पूरी तरह झुके होने की स्थिति को दर्शाता है। एक व्यक्ति की अमानवीय हत्या को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में खुशी-खुशी प्रसारित किया गया, जिसमें दर्जनों हमलावरों को मृत शरीर को रौंदते हुए और बाद में उसके क्षतविक्षत शरीर को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया। यह सब बांग्लादेशी समाज में बढ़ती बर्बरता को उजागर करता है।

दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रमुख विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर सरकार की चुप्पी की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार के मौन रहने पर हमला बोला है, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इतनी बर्बरता के सामने केंद्र के चुप रहने को निंदा की है।

पिछले सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश अराजकता की स्थिति में है, जब बड़े जनविद्रोह के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थीं। तब से एक अंतरिम सरकार सत्ता में है, जिसके दौरान अपराध और हिंसा का बोलबाला रहा है।

यह सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जमातियों की मदद से कराया था और इसके बाद से इस्लामी हिंसा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। वर्तमान हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एक राजनीतिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कई अन्य लोगों पर भी हमले हुए और अब पूरे देश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद से देश में थोड़ी भी व्यवस्था लाने में पूरी तरह नाकाम रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑपरटर कई कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रित कर रहे हैं।

अंकिता भंडारी मर्डर, एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रहे हैं कि गौतम ने ऋषिकेश के पास एक रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि

राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में, उत्तराखंड कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा नियंत्रित केंद्र और राज्य सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

पार्टी ने धमकी दी है ऐसा नहीं हुआ तो गढ़वाल मंडल के प्रमुख कार्यालय में धरना और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने इस “भयंकर और नृशंस हत्या” की सीबीआई जांच की मांगों को नज़रअंदाज किया है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, गोदियाल ने कहा, कि

भाजपा के प्रभावशाली लोग इस मामले में संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

गोदियाल के अनुसार, केंद्रीय जांच “जानबूझकर रोक की गई” क्योंकि यह रिसॉर्ट कथित तौर पर शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो “अवैध और अमानवीय गतिविधियों” में शामिल थे। उन्होंने इस मामले में शामिल सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई गैर-भाजपा राजनीतिक दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है जो इस युवा लड़की के यौन शोषण और हत्या में कथित रूप से शामिल हैं। वायरल वीडियो ने यह सुनिश्चित किया है कि अंकिता भंडारी मामला फिर से राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है, और सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस पर निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दे।

TRUE VALUE

इस क्रिसमस कार लेना हुआ आसान । सिर्फ ₹59 प्रतिदिन# की आसान किश्तों में ।

CELEBRATING 60Lakh

STORIES OF TRUST

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

QR

Download on the App Store

QR

GET IT ON Google play

ट्रस्ट

✓

वेरिफाइड कार हिस्ट्री**

✓

3 फ्री सर्विसेज** 5000 से अधिक मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशनों पर उपलब्ध

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruvalue.com

*नियम एवं शर्तें लागू। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निकटतम डीलरशिप पर संपर्क करें। **वेरिफाइड कार हिस्ट्री और वारंटी केवल दू वैल्यू प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। दर्शाई गई छवियाँ केवल प्रतिनिधिक उद्देश्य के लिए हैं। *ऋण राशि ₹1 00 000 मानी गई है। ऋण की अवधि 84 महीने @ 80।11% वार्षिक ब्याज दर पर ली गई है। डाउन पेमेंट कार के मूल्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। फाइनेंस पूरी तरह बैंक या वित्तीय संस्था की मंजूरी पर निर्भर है और ग्राहक प्रोफाइल के अनुसार बदल सकता है।

क्वालिटी

✓

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

✓

1 साल तक की वारंटी**

TRUE VALUE CERTIFIED

आसान फाइनेंस विकल्प* उपलब्ध हैं ।

ALWAR: NEAR ALWAR PUBLIC SCHOOL, JAIPUR ROAD, ALWAR, MG MOTORS: 7240012934, 7728892248, 7073130666 | OPPOSITE MATILA POLICE STATION ALWAR BYPASS ROAD BHIWADI, FORTUNE CARS: 8875001550, 9214094335 | MANHAR VILLA, NEAR JAIL CIRCLE, VIJAY NAGAR ROAD, ALWAR, FORTUNE CARS: 7230029310, 7230029304. BHARATPUR: AFTER BARSO, BEFORE SHAHEED PETROL PUMP, AGRA ROAD, BHARATPUR, T.M. MOTORS: 9772965965, 9772772999.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.ए.ई. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधमा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैंन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908